



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 136]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 17, 1986/ज्येष्ठ 27, 1908

No. 136]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 17, 1986/JYAISTHA 27, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके ।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
separate compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 17 जून, 1986

संकल्प

संख्या आर. 17011/34/85-सी. एण्ड जी.—राष्ट्रपति ने यह
निर्णय किया है कि स्वीडिश संगठनों की सहायता के लिए एक स्थायी
समिति गठित की जाए जो तत्काल प्रभावी हो ।

2. इस समिति की संरचना इस प्रकार होगी :-

- | | |
|--|---------|
| 1. श्रीमती मस्मिता श्रीवास्तव अध्यक्ष, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली | अध्यक्ष |
| 2. श्रीमती विद्या बेन शाह, अध्यक्ष, भारतीय बाल कल्याण परिषद्, नई दिल्ली | सदस्य |

- | | |
|---|-------|
| 3. डा. (श्रीमती) ललिता राव, अध्यक्ष, भारतीय आयुर्विज्ञान संघ, नई दिल्ली | सदस्य |
| 4. श्रीमती जया अण्णाचलम अध्यक्ष, वकिंग वीमन्स फोरम, मद्रास | सदस्य |
| 5. श्रीमती वेर्ना डब्ल्यू. इंग्ली, अध्यक्ष, मेघालय राज्य समाज कल्याण बोर्ड, शिलांग | सदस्य |
| 6. डा. (कु.) रजनी बहल, वनवासी सेवा आश्रम, मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) | सदस्य |
| 7. श्रीमती नलिनी नायक, पी. सी. ओ. सेंटर, केरल | सदस्य |

8. श्रीमती रामी छाबड़ा,
सीडिया एक्सपर्ट,
भारतीय परिवार नियोजन प्रतिष्ठान,
नई दिल्ली
9. कु. मीरा सेठ,
अपर सचिव एवं आयुक्त (प.क.),
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)
10. श्री आर. एम. मोंगैव,
संयुक्त सचिव (विशेष सलाहकार),
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
11. डा. लता सिंह,
संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

सदस्य

पदेन सदस्य

पदेन सदस्य

संयोजक और
सदस्य सचिव

क-7—अस्य सेवाएं और सामग्री क-7(10)—अस्य योजनाएं क-7(10)
(6) स्वीच्छक संगठनों का सहयोग, क-7(10)(6)(1) सहायता—
अनुदान के अंतर्गत स्वीकृत बजट अनुदान से धन किया जाएगा। इस
खर्च को "प्लान खर्च" के अंतर्गत नुक किया जाता है।

लता सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(Deptt. of Family Welfare)

New Delhi, the 17th June, 1986

RESOLUTION

No. R. 17011/34/85-C&G:— The President has been pleased to decide that a Standing Committee for support to Voluntary Organisations should be constituted with immediate effect.

2. The composition of this Committee will be as under:—

1. Smt. Sasmeeta Srivastava, —Chairman
Chairman,
Central Social Welfare Board,
New Delhi
2. Mrs. Vidya Ben Shah, —Member
Chairman,
Indian Council of Child Welfare,
New Delhi
3. Dr. (Mrs.) Lalita Rao, —Member
President,
Indian Medical Association,
New Delhi
4. Mrs. Jaya Arunachalam, —Member
President,
Working Women's Forum,
Madras
5. Smt. Verma W. Ingty, —Member
Chairman,
Meghalaya State Social Welfare Board,
Shillong
6. Dr. (Ms.) Rajni Behn, —Member
Banwasi Seva Ashram,
Mirzapur (UP)
7. Mrs. Nalini Nayak, —Member
PCO Centre,
Kerala
8. Smt. Rami Chabra, —Member
Media Expert,
Family Planning Foundation of India,
New Delhi
9. Miss. Mira Seth, —ex-officio
Additional Secretary
& Commissioner (FW),
Ministry of Health & F.W.,
New Delhi.
10. Shri R.M. Bhargava, —ex-officio
Joint Secretary (FA),
Ministry of Health & F.W.,
New Delhi.
11. Dr. Lata Singh, —Convener &
Joint Secretary,
Ministry of Health & F.W.,
New Delhi.

3. समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे:—

- (i) ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी गरीब वर्गों में आधार्मिक स्तर पर कार्य कर रहे स्वीच्छक एजेंसियों के जल्दा-जल्दा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन से संबंधित परिवार कल्याण परियोजनाओं को स्थापित करने, स्वास्थ्य मानकों में सुधार लाने और स्वीच्छक संगठनों के वर्तमान कार्यों को परिवार कल्याण के साथ जोड़ने से संबंधित आवेदनों पर विचार करना और जो व्यावहारिक पाए जाएं उन्हें सहायता अनुदान देने की सरकार को सिफारिश करना।
 - (ii) ऐसी नई विचारधाराएं और नीतियां तैयार करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना जिनसे कि अंततः कम लागत पर लोगों के स्वास्थ्य स्तरों में सुधार होगा और ग्रामीण क्षेत्रों तथा उन क्षेत्रों के लोग अधिक आत्म-निर्भर हो आएंगे जहां ये सेवाएं उपलब्ध नहीं की गई हैं।
 - (iii) चिकित्सा विज्ञान की परम्परागत पद्धतियों को अपनाने वालों परियोजनाओं को स्वीकार करना तथा उन पर विचार करना ताकि अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।
 - (iv) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य कर रहे सभी स्वीच्छक संगठनों का लेखा-जोखा रखना और उनकी सूची बनाना।
 - (v) इस प्रकार के आधार्मिक स्तर के अनुभवों का लाभ उठाने के लिए स्वीच्छक एजेंसियों को केस-स्टडी/प्रोफाइल तैयार करना जिनका उपयोग नीति तैयार करने और ऐसी नई योजनाएं तैयार करने के लिए किया जा सकेगा जो गरीबों की रक्षा से नीचे के वर्गों के लिए अधिक उपयुक्त होंगी।
4. परियोजना के लिए सिफारिश किया गया सहायता अनुदान परियोजना अवधि के लिए जो एक से तीन वर्ष की हो सकती है, एक लाख रुपये से अधिक नहीं होगा।
5. गैर-सरकारी सदस्यों के कार्यालय की अवधि 3 वर्ष होगी और तिहाई सदस्य हर वर्ष सदस्यता छोड़ने रहेंगे।
6. समिति जब आवश्यक समझेगी तब अपनी बैठकें आयोजित करेगी।
7. गैर-सरकारी सदस्यों के बैठक में भाग लेने के लिए यात्रा-भत्ता और दैनिक भत्ते पर होने वाला खर्च एस. आर. 190 के उपबन्धों और सरकार द्वारा इसके लक्ष्य समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अंतर्गत नियमित किया जाएगा।
8. इस पर होने वाला खर्च वर्ष 1986-87 के लिए भाग संख्या 46 परिवार कल्याण के अंतर्गत मुख्य लेखा शीर्ष 281—परिवार कल्याण,

3. The terms of reference of the Committee will be as under:—

- (i) To consider applications received from voluntary agencies working at the grass-root level in the rural and urban slums for setting up Family Welfare Projects relating to MCH, Family Planning, Improvement in Health standards and those which integrate the present activities of voluntary organisations with Family Welfare and recommend those found feasible to Government for release of grant-in-aid.
- (ii) To encourage community action to generate new ideas and approaches that will ultimately lead to the improvement of health standards of the people at reduced costs and create greater self-reliance in the rural and unserved areas.
- (iii) To entertain and consider projects adopting the traditional systems of medicine for achieving the desired purpose.
- (iv) To document and list all voluntary organisations (agencies) working in specific areas concerned with the Ministry of Health and Family Welfare.
- (v) To prepare case studies/profiles of voluntary agencies to draw lessons from such grass-root experiences which could be used to influence policy and draw up new

schemes more suitable for target groups living below the poverty line.

4. The grant-in-aid recommended for a project shall not exceed Rs. 1 lakh for the project period which may vary from one to three years.

5. The term of office of non-official members will be for a period of 3 years with 1/3rd of the members relinquishing office every year.

6. The Committee will hold its meetings as often as necessary.

7. T.A. and D.A. to non-official members for attending the meetings of the Committee shall be regulated in accordance with the provisions of S.R. 190 and orders of the Government of India thereunder as issued from time to time.

8. The expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant under the Major Head of account 281-Family Welfare, A. 7-Other Services and Supplies, A. 7 (10)-Other Schemes, A. 7-(10) (6)-Involvement of Voluntary Organisations, A. 7(10)(6)(1)-Grant-in-aid, under Demand No. 46 Family Welfare for the year 1986-87. The expenditure is to be booked as 'Plan Expenditure'.

LATA SINGH, Jt. Secy.